

प्रेषक,

शानुज्ज सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संदा मे,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-२

देहरादून: दिनांक- ३१ अक्टूबर, २००७

विषय : नगर पंचायत, लंडौरा के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष-२००६-०७ में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष २००७-०८ में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० ६९२/V-श०वि०-०६-५०(सा०)/०६, दिनांक २५-३-०६ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पंचायत, लंडौरा जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत छ. कार्यों हेतु रु०-१२१.०८ लाख की लागत के आगणन के विपरीत रु०-१२१.०० लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० ४९.५८ लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र सं० १९३२/श.वि.नि.-४८५-२००५/लेखा/०७-०८ दिनांक ०७ अगस्त २००७ के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अवमुक्त धनराशि के उपयोग के उपरांत, शासनादेश दिनांक २५-३-०६ के माध्यम से स्वीकृत कार्यों हेतु रु. ४०.०० लाख (रुपये चालीस लाख मात्र) की द्वितीय किश्त की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निनालिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

१. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बित नगर पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी जो कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से अन्य शर्त पूर्ण करने पर अवमुक्त करेंगे।
२. शासनादेश सं० ६९२/V-श०वि०-०६-५०(सा०)/०६, दिनांक २५-३-०६ में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
३. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
४. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अप्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
५. स्वीकृत धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग करते हुए कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
६. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिकारी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
७. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपर्युक्त पार्यी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
८. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादरा संख्या २०४७/XIV-२१९/२००६ दिनांक ३०मई, २००६ के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।
९. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक ३१.३.२००८ तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी उपलब्ध करा दिया जायेगा, आगामी किश्त तथ ही अवमुक्त की जायेगी जब उक्त विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

२- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष २००७-०८ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या १३ के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "२२१७-शहरी विकास-०३- छाट तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-१९१-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-०३-नगरों का समेकित विकास-०५- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '२० सहायक अनुदान/अंशदान/ सज सहायता के नामे छाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के अशा०स०— 483 / XXVII(2) / 2007, दिनांक— ०८ अक्टूबर, 2007 ने प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शनुज्जन सिंह)
सचिव।

सं-३६८(१) / वा०वि०-०७ तददिनांक ३१/१०/०८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/ नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग—२/ वित्त नियोजन प्रकौश्ल, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. ✓ निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, लंडौरा।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आङ्गा से,

मायावती
(मायावती डकरियाल)
अनु सचिव।